वर्ष : 02- अंक : 24 - मार्च 2025

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार उदय

सहकारिता में सुधार

कोऑपरेटिव बैंक हो रहे सशक्त

'छोटे लोगों का बड़ा बैंक' के सूत्र को जनता सहकारी बैंक ने किया सार्थक 10

देशवासियों की यात्रा में सुगमता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 12

सहकार उदय

मार्च 2024, अंक 24, वर्ष 02

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
संतोष कुमार शुक्ला

संपादक
रोहित कुमार

सह संपादक
अँक अँजलीदीप

सदस्य
माधवी एम. विप्रदास
विवेक सक्सेना
हितेंद्र प्रताप सिंह
राशिद आलम

सहकार उदय से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

sahkaruday@iffco.in

महाप्रबंधक (सहकारिता विकास)
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

इफको से जुड़ने के अन्य पते:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

प्रकाशक-इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
मुद्रक-रॉयल प्रेस, बी-81, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

सहकारिता में सुधारः कोऑपरेटिव बैंक हो रहे सशक्त

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारिता में सुधार की प्रक्रिया को गति मिली है और सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में मंत्रालय ने सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने की पहल कारगर साबित हो रही हैं।

आवरण कथा

पेज 06 देखें

पेज 14 देखें

विकसित भारत बनाने में इन्वेस्टमेंट समिट की होगी अहम भूमिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं और 140 करोड़ जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

पेज 22 देखें

देश में शत प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के लिए सहकारिता ही एकमात्र विकल्प

पेज 24 देखें

'सबका इलाज- सबको आरोग्य' ही है 'सबका साथ-सबका विकास'

पेज 28 देखें

महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियां भारत में आर्थिक विकास को दे रही हैं बढ़ावाः संघाणी

पेज 16 देखें

विकसित भारत का ताना बाना बुन रहा टेक्सटाइल सेक्टर

भारत टेक्स अब एक जबरदस्त वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम बन गया है। यह दुनिया भर के नीति निमार्ताओं, सीईओ और उद्योग जगत के नेताओं के लिए व्यवसाय, सहयोग और साझेदारी का एक मजबूत मंच बन रहा है।

पेज 18 देखें

पूर्वोत्तर के बिना भारत और भारत के बिना पूर्वोत्तर अधूरा : श्री अमित शाह

पेज 19 देखें

जनजातीय समाज का उत्थान व उनका सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता

पेज 20 देखें

वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा भारत

सहकारी बैंकों की बदल रही सूरत

बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होती है। यह न केवल व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली मुख्यतः सहकारी बैंकों पर निर्भर करती है क्योंकि उनका नेटवर्क और व्यावसायिक क्षमता व्यापक है। सहकारी क्षेत्र में वित्त का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सहकारी बैंकों की त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं।

विगत वर्षों में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं ताकि इसकी कार्यक्षमता, पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ाया जा सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के अथक प्रयासों से सहकारी बैंकों के कारोबार में नियामकीय, संरचनात्मक, वित्तीय तथा ग्राहक केंद्रित सुधार को शामिल करते हुए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को शहरी सहकारी बैंकों और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों पर अधिक नियंत्रण दिया गया। इससे पारदर्शिता और बैंकिंग मानकों में सुधार हुआ है।

सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए संघटित बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत छोटे सहकारी बैंकों का विलय किया गया ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। पहले सहकारी बैंकों में जमा राशि पर एक लाख रुपए तक का बीमा कवर था, जिसे पांच लाख रुपए कर दिया गया है। संकटग्रस्त सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्पूंजीकरण योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बैंकों का पुनर्गठन कर सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता और स्थिरता में वृद्धि हुई है।

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण सहकारी बैंकों को अब आधार सक्षम भुगतान प्रणाली पर लाया जा रहा है। इससे सहकारी क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आएगी। साथ ही, बैंकिंग सेवाएं और तेज व पारदर्शी होंगी। निःसंदेह, वर्तमान भारत सरकार के भगीरथ प्रयास सहकारी बैंकों को अधिक सक्षम और भरोसेमंद बनाने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इससे आने वाले वर्षों में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र भारत के समग्र वित्तीय ढांचे में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा।

'सहकार उदय' पत्रिका के इस अंक में 'सहकारी बैंकिंग' विषय पर सारगर्भित आलेखों के साथ अन्य उपयोगी जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। हमें विश्वास है कि यह अंक आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगा।■

सादर धन्यवाद

जय सहकार

बीते एक दशक में हमने अपने गरीब भाई-बहनों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर मिशन मोड पर काम किया है, जिससे उनका जीवन बहुत आसान हुआ है। हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने के अपने लक्ष्य की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कुपोषण और एनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

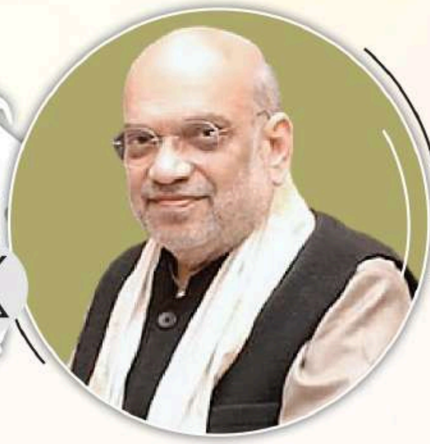

मोदी सरकार द्वारा किसान कल्याण की दिशा में शुरू की गई #पीएम किसान करोड़ों छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बीते 6 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंची है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

गाँव के स्तर पर किसानों एवं संबंधित व्यवसायों को मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी समितियों का अहम सहयोग रहा है। सहकारी समितियों को ताकत देने का कार्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

श्री मुरलीधर मोहोल, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

किसानों के विकास के लिए, कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की घोषणा की। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई।

श्री दिलीप संघाणी अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

बेहतर उपज, स्मार्ट खेती और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध इफको कृषि क्षेत्र को तकनीक की मदद से नई पहचान दे रहा है। विज्ञान और नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए इफको हमेशा आगे रहेगा।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इफको

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में, भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रमुख झलकियाँ, जो देशभर में 'सहकार से समृद्धि' के महत्व को व्यापक रूप से प्रदर्शित करते हुए लोगों के बीच सहयोग तथा एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे रही हैं।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मिले श्री दिलीप संघाणी

सहकारिता के आधुनिकीकरण में सरकार के प्रयासों की इफको अध्यक्ष ने की प्रशंसा

सहकार उदय टीम

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के माध्यम से भारत वैश्विक सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। जैसे-जैसे देश अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए तैयार हो रहा है, सहकारी समितियों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में और अधिक एकीकृत करने और लाखों आजीविकाओं पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इफको और एनसीयूआई के चेयरमैन श्री दिलीप संघाणी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें सहकारी क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने '*सहकार से समृद्धि*' के विजन को आगे बढ़ाने और भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने पर चर्चा की।

सहकारी क्षेत्र के देश के प्रमुख नेता की प्रधानमंत्री से हुई यह उच्च स्तरीय बैठक आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रगति में सहकारी समितियों का लाभ उठाने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संसद भवन में 30 मिनट तक चली इस बैठक में श्री दिलीप संघाणी ने सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे सक्रिय समर्थन की सराहना की। प्रधानमंत्री से मुलाकात पर श्री संघाणी ने कहा, 'मैंने पीएम मोदी को सहकारी क्षेत्र में हुए विकास और सहकारी पहलों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सहकारी क्षेत्र की प्रगति में गहरी रुचि दिखाई।

- अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की प्रगति से कराया अवगत
- '*सहकार से समृद्धि*' के विजन को आगे बढ़ाने और भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा

वे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे।'

इस बैठक में चर्चा का प्रमुख फोकस अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में भारत की सक्रिय भागीदारी थी। श्री संघाणी ने पूरे वर्ष के दौरान सहकारी क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पीएम को दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने पूरे वर्ष आयोजित होने कार्यक्रमों और गतिविधियों का एक कैलेंडर बनाया है। साथ ही, देश की सभी सहकारी संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र से जुड़े सेमिनार, वर्कशॉप, गोष्ठी, चर्चाएं एवं जागरूकता बढ़ाने वाले अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेंगे।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया था।

श्री संघाणी ने प्रधानमंत्री से हुई बातचीत को सहकारी क्षेत्र के लिए उपयोगी और उत्साहजनक बताया। उन्होंने डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय सहायता और शासन सुधार जैसी प्रमुख पहलों को स्वीकार किया, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ■

सहकारिता में सुधार

कोऑपरेटिव बैंक हो रहे सशक्त

सहकार उदय टीम

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारिता में सुधार की प्रक्रिया को गति मिली है और सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में मंत्रालय ने सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने की पहल कारगर साबित हो रही हैं। सहकारी बैंकों को भी प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की तर्ज पर कारोबार करने की अनुमति दी गई है। पारदर्शी कार्यप्रणाली और दायित्व निर्धारित करने के लिए सहकारी बैंकों का कंप्युटरीकरण किया गया है।

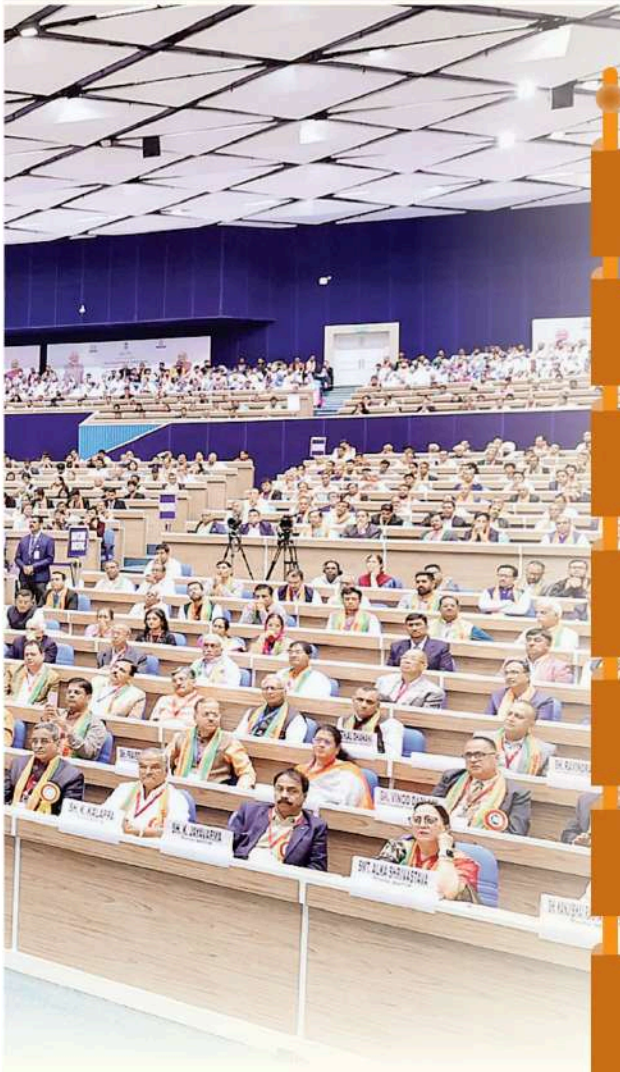

कोऑपरेटिव बैंकों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल

- शहरी सहकारी बैंक अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अब नई शाखाएं खोल सकेंगे
- सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह दिए गए कर्ज का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे
- ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत होम लोन की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ाई गई है
- शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को 'डोर स्टेप बैंकिंग' सेवाएं प्रदान करने दी अनुमति
- सभी सहकारी बैंकों को सीजीटीएमएसई योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में पात्र बनाया गया है
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक शीर्ष संगठन नैफकब की स्थापना की गई है
- ग्रामीण सहकारी बैंक अब कॉमर्शियल एवं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज दे सकेंगे ताकि उनके कारोबार का विविधिकरण हो सके

केंद्रीय वित्त मंत्रालय सहकारी बैंकों को निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने के लिए सहयोग कर रहा है। सुधार की इस प्रक्रिया से सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह दिए गए कर्ज का एकमुश्त निपटान करने में समक्ष होंगे। इतना ही नहीं, शहरी सहकारी बैंक अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोल सकेंगे। ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत होम लोन की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ा दी गई है। इससे उनके व्यावसायिक कारोबार का दायरा बढ़ जाएगा और सहकारी बैंकों के व्यवसाय में विविधीकरण को बल मिलेगा। सहकारी बैंक भी आगे बढ़कर उपभोक्ताओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। शहरी बैंको को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में पात्र बनाया गया है।

शीर्ष संगठन नैफकब का गठन

शहरी सहकारी बैंकों के कामकाज की निगरानी के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से प्राप्त होने वाली वित्तीय मदद की समीक्षा के लिए नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) का गठन किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों के इस शीर्ष संगठन के अस्तित्व में आने के बाद सहकारी बैंकों की कार्य कुशलता में सुधार हुआ है। सहकारी बैंकों के समक्ष आने वाली कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों के सशक्तिकरण के लिए हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सहकारी बैंकों की तमाम खामियों और कमजोरियों को दूर कर उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करने और मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे

हैं। इसका असर अब विभिन्न सहकारी बैंकों में दिखने भी लगा है। सहकारी बैंकों का परिचालन निजी और सार्वजनिक बैंकों की तरह करने के प्रयास किए जा रहे है। इससे जहां सहकारी बैंकों के ग्राहकों को अन्य बैंकों की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी, वहीं ग्राहक आधार का विस्तार होने से उनका कारोबार भी बढ़ेगा।

सहकारी बैंकों में ही खाता खोलने के निर्देश

कोऑपरेटिव बैंकों के परिचालन में पहले सबसे बड़ी बाधा नियामक संस्थाओं की अनिश्चितता थी, क्योंकि सहकारी बैंकों का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न सहकारी कानूनों के तहत होता था। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए इनके नियामक संस्था की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सौंपी गई है। कोऑपरेटिव बैंकों को कॉमर्शियल बैंकों की तरह कामकाज करने, लोन एवं अन्य सेवाएं देने की मंजूरी देने के साथ-साथ उनके ऑडिट सिस्टम में सुधार की पहल की गई है।

डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा

सहकारी बैंकों के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से किए गए महत्वपूर्ण पहलों में शहरी सहकारी बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने, आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम को कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खोलने, ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, वाणिज्यिक बैंकों की तरह कर्ज का एकमुश्त निपटान करने, ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत होम लोन की सीमा दोगुनी से अधिक करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह, ग्रामीण सहकारी बैंक अब कमर्शियल एवं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज दे सकेंगे, ताकि उनके कारोबार का विविधिकरण हो सके।

सहकारी बैंकों में पांच लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिपॉजिट

वर्तमान में देश में कुल 1,465 शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें से लगभग आधे गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। देश में 49 शेड्यूल्ड बैंक हैं और 8.25 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। शहरी सहकारी बैंकों की 11,000 शाखाओं, 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट और 3.50 लाख करोड़ रुपए के ऋण के साथ सहकारी बैंकी की सामूहिक स्थिति मजबूत हुई है। सरकार ने हर शहर में शहरी सहकारी बैंक बनाने और अगले पांच साल में देश के 80 जिलों में जिला सहकारी बैंक खोलने का लक्ष्य तय किया है। अभी देश में 352 जिला सहकारी बैंक हैं जिनमें कुल 4.33 लाख करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि 34 राज्य सहकारी बैंकों में 2.42 लाख करोड़ रुपए जमा हैं।

सहकारिता में सहकार को प्रोत्साहन

सहकारिता में सहकार के सिद्धांत के तहत कोऑपरेटिव संस्थाओं का सारा लेनदेन और वित्तीय व्यवहार कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही करने की शुरूआत की गई है। सहकारिता में सहकार के सिद्धांत को देश के सभी राज्यों में जमीन पर उतारने से ही सहकारिता क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा। इस देशव्यापी कदम से न सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों को पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है, बल्कि उनका कारोबार भी कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। इन बैंकों का कारोबार बढ़ेगा तो नौकरियों के नए अवसर भी बढ़ेंगे। देश के करीब 30 करोड़ लोग सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे में, जब इन सभी लोगों का खाता कोऑपरेटिव बैंक में खुलेगा, तो इन बैंकों का कारोबार कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा, सभी तरह के पैक्स और अन्य सहकारी समितियों के भी खाते कोऑपरेटिव बैंक में खुलने से गांवों और दूरदराज के इलाके में स्थित इन बैंकों के कारोबार में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी।

बैलेंस शीट और लेखा मानकों में बदलाव

कोऑपरेटिव बैंकों के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और आरबीआई लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए बैलेंस शीट और अकाउटिंग के प्रारूप में बदलाव किया है। अब सहकारी बैंकों के लिए वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस तक अपनी बैलेंस शीट और लाभ एवं

सभी सुविधाओं से लैस होंगे कोऑपरेटिव बैंक

कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अंब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) बनाया गया है जो एक नियामक की तरह काम करेगा। इस संगठन के लिए 300 करोड़ रुपये एकत्रित करने का काम पूरा कर लिया गया है। यह अंब्रेला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने में सक्षम होगा। एनयूसीएफडीसी के मुंबई स्थित कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन 24 जनवरी, 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक अगले तीन साल में राष्ट्रीय बैंकों और निजी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं से युक्त हो जाएंगे जिनसे इनकी सेवाओं का विस्तार होगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और विदेश के साथ व्यापार जैसी गतिविधियों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ समाहित करने का काम 'अंब्रेला संगठन' करेगा। इसके साथ-साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार और सभी कोऑपरेटिव बैंकों के अकाउंटिंग सिस्टम को एक करना इसका लक्ष्य रहेगा। सेवाओं का विस्तार होगा तो इन बैंकों का भी विस्तार होगा। बैंकों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

सहकारी बैंकों से माइक्रो एटीएम कार्ड

किसानों और डेयरी क्षेत्र में लगे पशुपालकों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात के दो जिलों बनासकांठा और पंचमहल और फिर पूरे गुजरात में चलाया गया था जिसे जबर्दस्त सफलता मिली। इसकी सफलता को देखते हुए अब इसे देशव्यापी बना दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को वित्तीय लेन-देन के लिए सदस्यों को माइक्रो एटीएम कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। सरकारिता से जुड़े सभी लोगों के बैंक खाते सहकारी बैंकों में ही खोले गए। इसके तहत सीमित अवधि में ही दोनों जिलों में चार लाख से अधिक बैंक खाते सहकारी बैंकों में खोले गए और 750 करोड़ रूपये की धनराशि जमा की गई। जबकि पूरे गुजरात में 9.40 लाख खाते खोले गए और 3,853 करोड़ रूपये की धनराशि जमा हुई। इससे सहकारी बैंकों के साथ उनसे जुड़े लोगों को काफी लाभ हुआ। अब सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस परियोजना के शुरू होने से सहकारी समितियों का वित्तीय लेन-देन आसान होगा। इस अभियान का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और राज्य स्तरीय सहकारी बैंक के माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है, जिससे सदस्यों को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो सकें। इस देशव्यापी परियोजना के शुरू होने के दो महीने के भीतर बैंक मित्रों की नियुक्ति और रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम पूरा कर लिया गया। देशभर में बैंक मित्रों की नियुक्ति से लाखों युवा लाभान्वित हुए हैं।

हानि का खाता तैयार करना आवश्यक हो गया है। यह बदलाव आधुनिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वित्तीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। इसका मकसद उभरते वित्तीय परिदृश्य और आधुनिक अकाउंटिंग मानकों के साथ तालमेल बिठाना है। इससे कोऑपरेटिव बैंक अब कमर्शियल बैंक की तरह अपना बैलेंस शीट दुरुस्त रख पाएंगे, जिससे गड़बड़ी की आशंका कम होगी। यह कदम कोऑपरेटिव बैंकों को न सिर्फ सशक्त बनाएगा, बल्कि इससे ग्राहकों के हितों की भी रक्षा होगी।

सहकारी क्लीयरिंग हाउस से भुगतान में तेजी

देश में पहली बार कोऑपरेटिव बैंकों के लिए क्लीयरिंग हाउस बनाने की पहल की गई है। कोऑपरेटिव बैंकों को सार्वजनिक एवं निजी बैंकों की तरह प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अब कोऑपरेटिव बैंक की क्लीयरिंग कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही की जाएगी। इसके लिए क्लीयरिंग हाउस बनाया जा रहा है जो अगले दो साल में अपनी सेवाएं देने लगेगा। इससे इन बैंकों को अब सार्वजनिक और निजी बैंकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे जहां क्लीयरिंग में तेजी आएगी, वहीं भुगतान भी जल्द हो सकेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंक, छोटे वित्तीय बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के लिए भी सरकार गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और तकनीकी नवाचार को समाहित करने के लिए एक निगरानी समिति बना रही है।

शहरी कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति सुधरी

सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने को लेकर उठाए कदमों से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) की स्थिति में सुधार होने लगा है। आरबीआई की 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति' रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से शहरी सहकारी बैंकों के पूंजी, मुनाफा और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। हालांकि, वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कर्ज और जमा में सहकारी बैंकों की धीमी वृद्धि इस क्षेत्र की चुनौतियों को दशार्ता है। आरबीआई के अनुसार, यूसीबी ने परिचालन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल के साथ प्रशासन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने में प्रगति की है। इनमें चार-स्तरीय नियामक संरचना की शुरूआत, बोर्ड के निदेशकों और आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के साथ सीधा जुड़ाव और आईटी एवं साइबर सुरक्षा जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बैंकों की ऋण और जमा वृद्धि अपेक्षाकृत स्थिर रही। वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण वृद्धि 5 प्रतिशत और जमा में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यूसीबी स्थिर ऋण-जमा अनुपात बनाए रखने में कामयाब रहे और यह बढ़कर 2023-24 में 62.5 प्रतिशत हो गया।

छोटे लोगों का बड़ा बैंक बन रहे सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों के सशक्तिकरण से शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन लोगों के वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी जो बैंकिंग सुविधा से अछूते हैं या फिर छोटे जमाकर्ता हैं। सहकारी बैंक छोटे लोगों का बड़ा बैंक का सूत्रधार है। इनकी मजबूती देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मददगार होगी।■

पुणे में जनता सहकारी बैंक के हीरक जयंती समारोह में बोले श्री अमित शाह

'छोटे लोगों का बड़ा बैंक' के सूत्र को जनता सहकारी बैंक ने किया सार्थक

सहकार उदय टीम

- बिना पूंजी के प्रगति करने और देश के विकास में योगदान देने का एकमात्र रास्ता है सहकारिता
- बैंक की 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशि लोगों के विश्वास को दर्शाता है
- 'कोऑपरेटिव क्लीयरिंग हाउस' बनाने की कल्पना अगले दो साल में हो जाएगी पूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के गठन का उद्देश्य '*सहकार से समृद्धि*' है। भारत को वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने और 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्पों को पूरा करने के लिए भी सहकारी क्षेत्र का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में जनता सहकारी बैंक लिमिटेड की हीरक जयंती समारोह में देश के विकास के लिए सहकारिता के विकास की अपरिहार्यता को दोहराते हुए अपने इन विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति का विकास न हो और हर घर में समृद्धि न हो तो भारत के विकास के उपरोक्त दोनों संकल्प अधूरे रह सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना और उसे देश के विकास के साथ जोड़कर हर परिवार को समृद्ध बनाना सिर्फ सहकारिता आंदोलन के माध्यम से संभव हो रहा है।

श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सहकारी विकास को दिशा देते हुए सहकारिता आंदोलन को गति और मजबूती प्रदान किया है। श्री शाह ने कहा कि देश के विकास में योगदान देने का एकमात्र रास्ता सहकारिता है।सरकार ने देश के कोऑपरेटिव के मॉडल को बाजार योग्य बनाया है। भारत सरकार ने सहकारी शिक्षा को सशक्त करने के लिए संसद में सहकारिता विश्वविद्यालय बिल पेश किया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारी नवाचार को जोड़ करके भारत सरकार इसे देश के विकास की शक्ति बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोगों की छोटी-छोटी पूंजी को मिलाकर एक बहुत बड़ा काम करने और बिना पूंजी के भी अपने परिवार

का विकास करने का नाम ही सहकारिता है। जनता सहकारी बैंक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसने 'छोटे लोगों का बड़ा बैंक' के सूत्र को सार्थक किया है। श्री शाह ने कहा कि इस बैंक ने जो जन विश्वास अर्जित किया है, वह हम सबके लिए गौरव का विषय है। वर्ष 1949 में स्थापना के बाद जनता सहकारी बैंक 1988 में शेड्यूल्ड सहकारी बैंक बना, 2005 में इसने कोर बैंकिंग को स्वीकार किया और 2012 में मल्टीस्टेट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक बना।

कोऑपरेटिव डी-मैट शुरू करने वाला पहला कोऑपरेटिव बैंक

देश की सबसे पहली कोऑपरेटिव डी-मैट संस्था शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले जनता कोऑपरेटिव बैंक की कार्य प्रणाली को सराहते हुए श्री शाह ने कहा कि यह 71 ब्रांच व दो एक्सटेंशन काउंटर के साथ 1,75,000 सदस्यों और 10 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहकों के साथ यह एक बैंक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा परिवार है। वर्तमान समय में बैंक की जमाराशि 9,600 करोड़ रुपए से अधिक है जो बैंक में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। श्री शाह ने कहा कि समाज सेवा में भी जनता सहकारी बैंक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे वह लातूर का भूकंप हो या फिर कोल्हापुर-सांगली की बाढ़ हो या कोविड महामारी का दौर हो।

सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए तकनीक की जरूरत

श्री शाह ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए हमें तकनीक को स्वीकारना होगा। देश में कुल 1465 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनमें से 460 बैंक महाराष्ट्र में ही हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) के लिए एक अंब्रेला संगठन पर विचार चल रहा था और अब इस संगठन के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की गई है। यह अंब्रेला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने में सक्षम होगा। पहली बार देश में 'कोऑपरेटिव क्लीयरिंग हाउस' बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसे अगले दो सालों में पूरा कर लिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि एकमुश्त ऋण निपटान का प्रावधान भी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए लागू होगा। अंब्रेला संगठन बनने के बाद देश के किसी भी हिस्से में स्थित कोऑपरेटिव बैंक की क्लीयरिंग कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही होगी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक, छोटे वित्तीय बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के लिए भी सरकार गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और तकनीकी नवाचारों को समाहित करने के लिए एक निगरानी समिति भी बना रही है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने बहुत सारे काम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के व्यापार को बढ़ाने के लिए किए हैं। आधार-इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खोला गया है। गोल्ड लोन और हाउसिंग लोन की सीमा को भी बढ़ाया गया है। ■

> जनता सहकारी बैंक की स्थापना श्री मोरोपंत पिंगले जी ने की। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और कभी किसी चुनौती को पीठ नहीं दिखाई। श्रद्धेय मोरोपंत जी द्वारा बोया गया बीज आज वट वृक्ष बनकर 10 लाख लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और यह हमारी संगठन की क्षमता और अच्छे व्यवहार का परिचायक है। इस बैंक ने पूरे देश में एक अच्छा संदेश दिया है कि पारदर्शिता, समर्पण और निष्ठा के साथ कोई संस्था काम करती है तो वह कितना आगे बढ़ सकती है।
>
> \- श्री अमित शाह
>
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो’ 2025 में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

देशवासियों की यात्रा में सुगमता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

- विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी क्षेत्र में अप्रत्याशित कायाकल्प और अभूतपूर्व वृद्धि की साक्षी बनेगी
- हरित प्रौद्योगिकी, ईवी, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधन के विकास पर भारत का विशेष जोर

सहकार उदय टीम

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार है। जैसे-जैसे भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर आगे बढ़ेगा, देश के ऑटो बाजार में अभूतपूर्व परिवर्तन और विस्तार होगा। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025’ के उद्घाटन के दौरान व्यक्त किया। भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का ऑटोमोटिव उद्योग शानदार है और भविष्य के लिए तैयार है। लोगों की आकांक्षाओं और युवाओं की ऊर्जा से प्रेरित होकर भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन देख रहा है। भारत में सालाना बिकने वाली कारों की संख्या कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। ‘मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड’ के मंत्र के चलते निर्यात बढ़ रहा है। पिछले एक साल में भारतीय ऑटो उद्योग में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस दौरान लगभग 2.5 करोड़ कारों की बिक्री भारत में लगातार बढ़ती मांग की सूचक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी अच्छी और चौड़ी सड़कों की कमी भारत में कार न खरीदने का एक कारण होता था, लेकिन देश में तेज गति से हो रहे सड़कों के निर्माण और सरकार की गंभीर पहल से अब यातायात स्थितियां बदल रही हैं। यात्रा-सुगमता भारत के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने भारत में ऑटो विनिर्माण के लिए एक पूर्ण तंत्र विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

पिछले चार वर्षों में ही इस क्षेत्र ने 36 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है और आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। देश में मल्टी-लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को गति दी है और लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स लागत वाला देश बनाएगी।

देश में ऑटो उद्योग के विकास के लिए अनुकूल हैं स्थितियां

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत कई दशकों तक दुनिया का सबसे युवा देश बना रहेगा जहां युवा सबसे बड़ा ग्राहक आधार होगा। देश की बड़ी युवा आबादी अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के जरिए नए वाहनों की उल्लेखनीय मांग पैदा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं और एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ है जो अपना पहला वाहन खरीद रहा है। देश में हो रहे विकास और लोगों की प्रगति का लाभ निरंतर ऑटो सेक्टर को मिलता रहेगा। अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ-साथ नई तकनीक को भी अपनाया जा रहा है। फास्टैग ने भारत में ड्राइविंग के अनुभव को बहुत आसान बना दिया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भारत में निर्बाध यात्रा के सरकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब कनेक्टेड वाहनों और स्वचालित ड्राइविंग में तेजी से प्रगति के साथ स्मार्ट मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है।

ऑटो उद्योग के विकास में 'मेक इन इंडिया' की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत के ऑटो उद्योग की विकास क्षमता में मेक इन इंडिया पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पीएलआई योजनाओं ने मेक इन इंडिया अभियान को नई गति दी है। इससे 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री में मदद मिली है। इस योजना ने इस क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। ऑटो क्षेत्र में रोजगार सृजन का अन्य क्षेत्रों पर भी कई गुना प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑटो क्षेत्र का विस्तार होने से एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधन के विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने

- देश में मल्टी-लेन हाईवे और एक्सप्रेस वे का हो रहा निर्माण
- पीएम गतिशक्ति योजना से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को गति और लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई
- पिछले एक साल में भारतीय ऑटो उद्योग में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि
- लगभग 2.5 करोड़ कारों की बिक्री भारत में लगातार बढ़ती मांग की सूचक
- दस वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 640 गुना वृद्धि, वर्ष 2024 में 16.80 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए

कहा कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी पहल इसी विजन को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का तेजी से हो रहा विकास

भारत में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तेजी से हुए विकास का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दस वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 640 गुना वृद्धि हुई है। दस साल पहले जहां केवल 2,600 इलेक्ट्रिक वाहन ही सालाना बेचे जाते थे, वहीं 2024 में 16.80 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब एक दिन में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या एक दशक पहले पूरे साल में बिकने वाले वाहनों की संख्या से दोगुनी है। उन्होंने इस दशक के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या आठ गुना बढ़ने की संभावना व्यक्त की। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए सरकार के नीतिगत निर्णयों और दिए गए सहायता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पांच साल पहले शुरू की गई फेम-2 योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सरकार ने दिए। इसके तहत 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों सहित 16 लाख से अधिक ईवी की खरीद के लिए सहायता दी गई। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 1,200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चल रही हैं। पिछले दिनों पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरूआत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इसके अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों सहित लगभग 28 लाख ईवी की खरीद में सहायता देगी।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सौर ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन को लगातार बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में ईवी और सौर ऊर्जा, दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। पीएम सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना, छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने के लिए एक प्रमुख मिशन है। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में बैटरी और भंडारण प्रणालियों की बढ़ती मांग का जिक्र कर कहा कि सरकार ने उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उन्होंने देश के युवाओं से ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान किया। देश के पर्यावरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा होगी।■

भोपाल में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' में श्री अमित शाह ने कहा

विकसित भारत बनाने में इन्वेस्टमेंट समिट की होगी अहम भूमिका

- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपए के हुए समझौते
- भारतीय कंपनियों, वैश्विक सीईओ, यूनिकॉर्न संस्थापकों और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने की भागीदारी

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं और 140 करोड़ जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यह इन्वेस्टमेंट समिट इन दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने में न सिर्फ सहायक होगा, बल्कि इनमें बहुत बड़ा योगदान भी देगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान इन विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की टीम इंडिया की कल्पना में भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को मिलकर आगे बढ़ने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे इस आयोजन ने आगे बढ़ाया है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कुल 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन किए गए। श्री शाह ने कहा कि इनमें से कई जमीन पर उतरेंगे और एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ-साथ सहायक उद्योगों को भी प्रदेश में स्थापित करने में सरकार की मदद करेंगे। श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की इन्वेस्टमेंट समिट ने न सिर्फ राज्य, बल्कि भारत के विकास को भी गति प्रदान किया है। इससे आने वाले दिनों में यह प्रदेश भारत के प्रमुख उद्योगों को स्थापित करने वाले राज्यों में शामिल होगा।

निवेश की आकांक्षा से 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी

श्री शाह ने कहा कि दो दिवसीय समिट में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां, 200 से अधिक वैश्विक सीईओ, 20 से अधिक यूनिकॉर्न संस्थापक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि प्रदेश में निवेश के इरादे से शामिल हुए हैं। इसमें मध्यप्रदेश ने अपने औद्योगिक, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमता का पता लगाने के सारे रास्ते खोलने का प्रयास किया है, जिससे राज्य के विकास को नया आयाम मिला है। श्री शाह ने कहा कि यह प्रदेश हमारे देश की भव्य सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है और प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'विकास भी विरासत भी' के सूत्र को चरितार्थ करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। राज्य में एक नए प्रयोग के तहत विकास के संकल्प के साथ हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग इन्वेस्टमेंट समिट का

आयोजन आने वाले दिनों में कई राज्यों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। श्री शाह ने कहा कि इस समिट में लोकल और ग्लोबल दोनों प्रकार के निवेश में वृद्धि करने के कई आयाम हासिल किए गए हैं। यह समिट भारत की अमृत पीढ़ी के लिए कौशल विकास के कई द्वार भी खोलेगी और भारत को 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने में भी बहुत सहायता करेगी।

पारदर्शी शासन ने निवेशकों को किया आकर्षित

श्री शाह ने कहा कि भारत के दिल जैसे मध्य प्रदेश में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुशल कार्यबल और पारदर्शी शासन एवं बेहतरीन प्रशासनिक तंत्र ने निवेश के अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर निवेश के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। प्रदेश में विस्तृत बाजार उपलब्ध है, जिससे मांग आधारित इकोनॉमी यहां तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूक्षेत्र, कार्यबल, खानों और खनिजों की उपलब्धता ने उद्योगों के लिए संभावनाओं और अवसरों को बढ़ाया है। श्री शाह ने कहा कि यह प्रदेश देश में सबसे अधिक खनिज संपदा वाले राज्यों में से एक है। इससे भारत का यह प्रदेश हर प्रकार से निवेश के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन गया है।

श्री शाह ने कहा कि एक जमाने में बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला यह प्रदेश पिछले 20 सालों में कुशल शासन की बदौलत बदल गया है। इस दौरान यहां पांच लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है। छह हवाईअड्डों वाले इस राज्य में 31 गीगावॉट की ऊर्जा क्षमता है जिसमें से 30 प्रतिशत 'क्लीन एनर्जी' है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), निफ्ट और एनआईएफडी जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान प्रदेश के युवाओं को इन मौकों के दोहन के लिए योग्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के 25 प्रतिशत ऑर्गेनिक कॉटन की सप्लाई यहीं से होती है। मध्य प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिए जनविश्वास विधेयक पारित करने वाला यह प्रदेश देश का पहला राज्य बना है।

पिछले 10 वर्षों में विकास की बुलंद इमारत पर गढ़े जाएंगे नए आयाम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के शासन में देश का विदेशी मुद्रा भंडार दो गुना हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दो गुना हो चुका है और प्रति व्यक्ति आय भी दो गुनी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में एक बहुत बड़ी और बुलंद इमारत की नींव डाली है और इस पर आने वाले दस सालों में भारत के विकास के कई नए आयाम गढ़े जाएंगे। मोदी सरकार ने इन वर्षों में देश के 54 करोड़ ऐसे लोगों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा है, जिनके पास आजादी के 75 वर्षों तक बैंक अकाउंट ही नहीं था। उन्होंने कहा कि दिवाला एवं दिवालियापन और एनपीए को 2.5 प्रतिशत से नीचे लाने, जीएसटी का सफल अनुपालन, 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के कई काम मोदी सरकार ने किए हैं। श्री शाह ने कहा कि इस दौरान देश में 60 हजार किलोमीटर राजमार्ग और आठ लाख किलोमीटर गांवों के रास्ते बने हैं, हवाईअड्डे 74 से बढ़कर 157 हुए हैं, रेलवे का विस्तार डबल हुआ है और कार्गो की हैंडलिंग में भी दो गुनी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत कई नई पहल करके आने वाले 25 सालों तक विश्व की आर्थिक दिशा तय करने वाले सेक्टर्स का संस्थापक बना है।■

'भारत टेक्स 2025' में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विकसित भारत का ताना बाना बुन रहा टेक्सटाइल सेक्टर

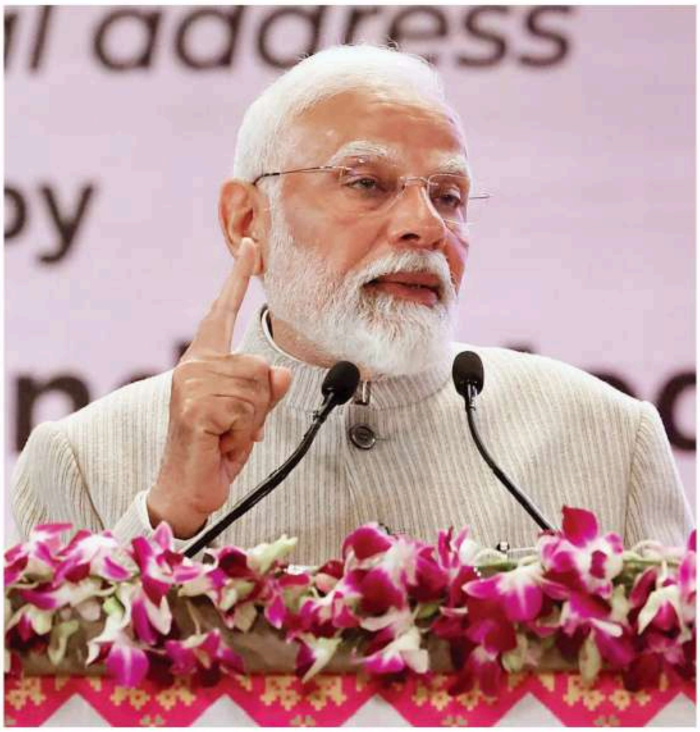

- दुनिया के नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के लिए व्यवसाय, सहयोग और साझेदारी का एक मजबूत मंच बन रहा भारत टेक्स
- हमारे पारंपरिक परिधानों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है भारत टेक्स
- एक साल में कपड़ा और परिधान निर्यात में सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ दुनिया में कपड़ा और परिधानों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत

सहकार उदय टीम

भारत टेक्स अब एक जबरदस्त वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम बन गया है। यह दुनिया भर के नीति निर्माताओं, सीईओ और उद्योग जगत के नेताओं के लिए व्यवसाय, सहयोग और साझेदारी का एक मजबूत मंच बन रहा है और इसमें 120 से अधिक देशों के हजारों उद्यमी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'भारत टेक्स 2025' के दौरान इन विचारों को देश और दुनिया के वस्त्र उद्योग से जुड़े हजारों प्रतिनिधियों के बीच साझा किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन कपड़ा क्षेत्र में निवेश, निर्यात और समग्र विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे रहा है। यह हमारी विरासत के साथ-साथ विकसित भारत की संभावनाओं की झलक भी दिखा रहा है, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। श्री मोदी ने कहा, 'पिछले साल भारत ने कपड़ा और परिधान निर्यात में सात प्रतिशत की वृद्धि देखी, और अब यह दुनिया में कपड़ा और परिधानों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है।' भारत का कपड़ा निर्यात तीन लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसे 2030 तक नौ लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कपड़ा क्षेत्र में सरकार के पिछले 10 वर्षों के लगातार प्रयासों और नीतियों का ही परिणाम है कि इस दौरान कपड़ा क्षेत्र में विदेशी निवेश दोगुना हो गया है।

कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत निर्णय ले रही सरकार

देश में वस्त्र उद्योग की प्राचीन विरासत का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा, 'भारत टेक्स

हमारे पारंपरिक परिधानों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है।' पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत में पारंपरिक परिधानों की एक विस्तृत श्रृंखला है। उन्होंने लखनऊ की चिकनकारी, राजस्थान व गुजरात की बांधनी, गुजरात की पटोला, बनारस की बनारसी सिल्क, दक्षिण भारत की कांजीवरम सिल्क और जम्मू-कश्मीर की पशमीना आदि विभिन्न प्रकार के परिधानों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के कपड़ा उद्योग की विविधता और विशिष्टता को बढ़ावा देने और इसके विकास को दिशा देने के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। श्री मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र का आह्वान किया कि वे कपड़ा क्षेत्र के उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करें, जिससे कि वस्त्र व्यवसाय का विस्तार हो और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। उन्होंने कहा, 'कपड़ा उद्योग देश में रोजगार के सबसे बड़े अवसरों में से एक है, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 11 प्रतिशत का योगदान देता है।' आम बजट 2025 में घोषित 'मिशन मैन्युफैक्चरिंग' का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश और विकास से करोड़ों कपड़ा श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। एमएसएमई से 80 प्रतिशत योगदान वाले कपड़ा क्षेत्र को इन उपायों से बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का समाधान करना और भारत के कपड़ा क्षेत्र की क्षमता को साकार करना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय कपास आपूर्ति सुनिश्चित करने और भारतीय कपास को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने और कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की कपड़ा मूल्य शृंखला को मजबूत करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। तकनीकी वस्त्र जैसे उभरते उद्योगों और स्वदेशी कार्बन फाइबर एवं इसके उत्पादों को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। भारत उच्च श्रेणी के कार्बन फाइबर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। भारतीय वस्त्र परंपरा की पारंपरिक टिकाऊ तकनीकों को अब अत्याधुनिक तकनीकों के साथ बढ़ाया जा रहा है, जिससे कारीगरों, बुनकरों और उद्योग से जुड़ी लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

विकसित भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र की होगी अहम भूमिका

श्री मोदी ने युवाओं को नए तकनीकी-वस्त्र स्टार्टअप लाने और नए विचारों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सुझाव दिया कि कपड़ा उद्योग नए उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी जैसे संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है। उन्होंने परंपरा को नवाचार के साथ जोड़ने और वैश्विक स्तर पर नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक परिधानों से प्रेरित उत्पादों को लॉन्च करने के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि पारंपरिक खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके फैशन के रुझानों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। खादी को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान 'खादी राष्ट्र के लिए' थी, लेकिन अब इसे 'खादी फैशन के लिए' होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सदियों पहले जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब कपड़ा उद्योग ने उस समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा, कपड़ा क्षेत्र एक बार फिर प्रमुख भूमिका निभाएगा। भारत टेक्स जैसे आयोजन इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा और हर साल नई ऊंचाइयों को छुएगा।

कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की भूमिका

कपड़ा उद्योग में कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में कुशल प्रतिभाओं का समूह बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की भूमिका का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मूल्य श्रृंखला के लिए समर्थ योजना आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायता कर रही है। प्रौद्योगिकी के युग में हथकरघा शिल्प कौशल की प्रामाणिकता बनाए रखने पर जोर देते हुए उन्होंने हथकरघा कारीगरों के कौशल व अवसरों को बढ़ाकर उनके उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा, 'पिछले 10 वर्षों में हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए 2400 से अधिक बड़े मार्केटिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।' हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत-हस्तनिर्मित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है, जिसने हजारों हथकरघा ब्रांडों को पंजीकृत किया है। हथकरघा उत्पादों के लिए जीआई टैगिंग से भी बड़े लाभ हो रहे हैं।

पूर्वोत्तर के बिना भारत और भारत के बिना पूर्वोत्तर अधूरा : श्री अमित शाह

सहकार उदय टीम

➲ पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य वर्ष 2027 तक दिल्ली से रेल व हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे

➲ सरकार ने पर्यटन, तकनीक, खेल, अंतरिक्ष, कृषि, उद्यमिता और बैंकिंग क्षेत्र से लेकर बिजनेस तक सभी क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट के लिए बढ़ाए अवसर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध किया है। पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने में सक्षम हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, खेल व अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए अपार अवसर हैं। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह असम राइफल्स के 'पूर्वोत्तर एकता उत्सव-एक आवाज, एक राष्ट्र' के आयोजन में हाल ही में नई दिल्ली में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि एकता उत्सव के समारोह ने पूर्वोत्तर की एकता व सांस्कृतिक ताकत को दिल्ली में स्थापित किया है। सरकार ने पर्यटन से तकनीक, खेल से अंतरिक्ष, कृषि से उद्यमिता और बैंकिंग से बिजनेस तक हर क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट के लिए अनेक अवसर बढ़ाए हैं।

पूर्वोत्तर भारत में खेलों की लोकप्रियता को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाने का निर्णय लिया। 'सभी के लिए खेल, उत्कृष्टता के लिए खेल' भारत में खेलों के विकास के सूत्र बने हैं। श्री शाह ने विश्वास जताया कि 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें भारत टॉप 10 में होगा और इसमें पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भूमिका होगी।

पूर्वोत्तर और दिल्ली के बीच मजबूत हुई कनेक्टिविटी

सरकार ने कनेक्टिविटी के माध्यम से पूर्वोत्तर और दिल्ली के बीच की भौतिक और दिलों की दूरी को समाप्त कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए सैकड़ों बजटीय प्रावधान बढ़ाए हैं और पूर्वोत्तर को तीन-चार गुना ज्यादा बजट दिया है। 2027 तक नॉर्थ ईस्ट के आठों राज्य रेल और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से देश की राजधानी के साथ जुड़ जाएंगे। पूर्वोत्तर भारत में 220 से अधिक जातीय समूह और 160 से अधिक जनजातियां रहती हैं, जहां 200 से अधिक बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, 50 से अधिक विशिष्ट उत्सव मनाए जाते हैं और 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य व 100 से अधिक व्यंजन अब भी अस्तित्व में हैं। यह सब पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी समृद्ध विरासत का खजाना है और हमारा देश इस विरासत पर गर्व करता है। श्री शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बिना भारत और भारत के बिना नॉर्थ ईस्ट अधूरा है।

शांति और विकास चाहता है नॉर्थ ईस्ट

श्री शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट अब शांति और विकास चाहता है और भारत के अभिन्न अंग के रूप में काम करना चाहता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों और विशेषकर पिछले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में कानून-व्यवस्था की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं और सुरक्षाबलों की मृत्यु में 70 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 85 प्रतिशत की कमी आई है। ■

आदिवासी छात्रों के साथ संवाद करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने बोला

जनजातीय समाज का उत्थान व उनका सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता

सहकार उदय टीम

- मोदी सरकार का 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले प्रखंडों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर
- कम से कम 20,000 आदिवासी लोगों वाले ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जनजातीय समाज को उसका वास्तविक सम्मान दे रही है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने और भारत की राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को चुनने जैसे सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों ने जनजातीय समाज के गौरव को एक नए शिखर पर पहुंचाया है। जनजातीय समाज का उत्थान व उनका सशक्तीकरण हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को नई दिल्ली में गुजरात के डांग जिले के ग्रामीण एवं आदिवासी समाज के छात्रों के साथ एक प्रेरक शैक्षणिक संवाद के दौरान व्यक्त किया। श्रीं शाह ने कहा कि मोदी सरकार 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना के माध्यम से आदिवासी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में आदिवासी छात्रों के लिए भाषा एक बाधा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने मातृभाषा में परीक्षा देने का विकल्प प्रदान किया है। इन फैसलों से आदिवासी छात्रों को एक नई उम्मीद मिली है। श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद के छह दशकों में देश में केवल एक ही केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय था, जबकि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार में दो नए आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किए।

देश की प्रगति के आधार हैं छात्र

छात्रों को प्रेरित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि छात्र देश की प्रगति की आधार हैं और उनका परिश्रम व समर्पण भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सेवक जैसे करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कहा कि यदि आप देश के विकास को अपना लक्ष्य बनाएंगे, तो इससे आपका व्यक्तिगत विकास स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित होगा। श्री शाह ने छात्रों को देश के विकास के लिए कार्य करने को अपना मूल उद्देश्य बनाने की सीख दी। उन्होंने छात्रों को परिश्रम और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में छात्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी सफलता ही भारत को अग्रणी बनाने में सहायक होगी।

इस विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम में छात्रों ने अपने अनुभवों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के साथ साझा किया। यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं आदिवासी समाज के छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत साबित हुआ और इसके माध्यम से उन्हें श्री शाह के साथ खुलकर संवाद करने का अवसर मिला। श्री अमित शाह की यह पहल युवाओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद और उन्हें प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस अवसर पर शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में छात्रों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने छात्रों के जिज्ञासाओं का समाधान किया और उन्हें मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प की महत्ता बताई। ■

'स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप' (सोल) लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

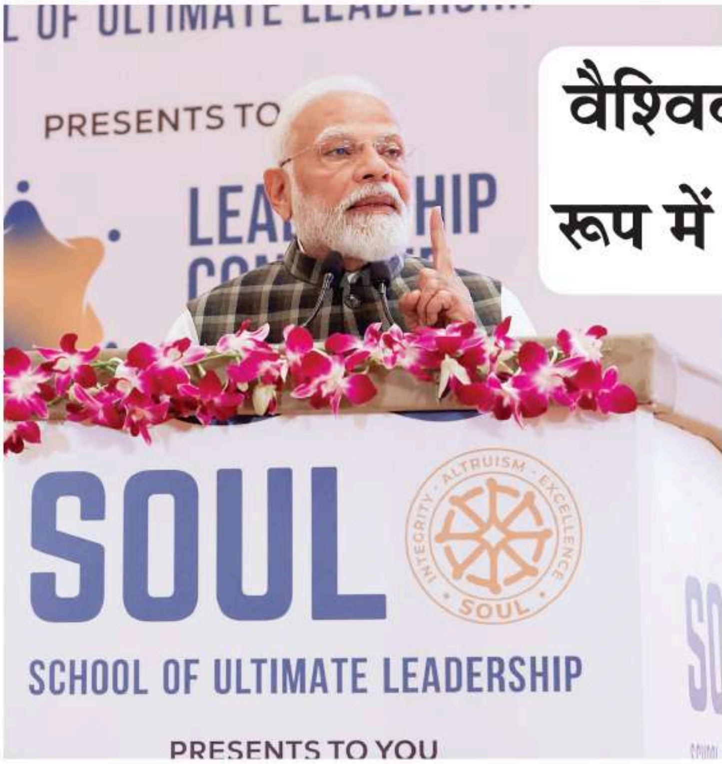

वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा भारत

- स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप ऐसे नेता तैयार करेगा जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करेंगे
- भारत को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो वैश्विक उत्कृष्टता के नए संस्थान विकसित कर सकें
- विकसित भारत के निर्माण के लिए बेहतर नागरिकों का विकास आवश्यक

सहकार उदय टीम

भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश की प्रगति में मानव और प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे नेतृत्व को तैयार करना समय की मांग है। विकसित भारत की विकास यात्रा में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (सोल) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सिर्फ संगठन का नाम नहीं है, बल्कि सोल भारत के सामाजिक जीवन की आत्मा होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप' (एसओयूएल) लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन के दौरान इन विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा, 'राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर नागरिकों का विकास आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है जो वैश्विक जटिलताओं का समाधान ढूंढ सकें, आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और साथ ही वैश्विक मंच पर राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दे सकें।' श्री मोदी ने कहा कि इन नेताओं का दृष्टिकोण वैश्विक होना चाहिए, लेकिन मानसिकता स्थानीय भी होनी चाहिए।

वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ाने की रणनीति

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मानसिकता को समझने वाले, रणनीतिक निर्णय लेने वाले, संकट प्रबंधन और भविष्य की सोच के लिए नेतृत्व तैयार करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजारों और वैश्विक संस्थानों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गतिशीलता को समझने वाले नेताओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोल की भूमिका ऐसे नेताओं को तैयार करना है, जिनका दायरा बड़ा हो और जिनसे उच्च अपेक्षाएं हों। सोल का उद्देश्य एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक शक्ति और भावना का संचार करना होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने घोषणा की कि जल्द में गुजरात की गिफ्ट सिटी के निकट सोल का एक नया और विशाल परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। इस उभरते हुए लीडरशिप संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक नेतृत्व को व्यापक बनाना और केवल राजनीतिक परिवारों तक सीमित न रखते हुए योग्यता, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना रखने वाले लोगों को आगे बढ़ाना है। यह संस्थान नेतृत्व से जुड़ी नई सोच, आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जिससे वर्तमान समय की जटिल दुनिया में नेतृत्व की चुनौतियों

स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (सोल) गुजरात में स्थापित हो रहा नेतृत्व संस्थान है जो विश्वसनीय नेताओं को सार्वजनिक भलाई के काम को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना और उन लोगों को शामिल करना है जो सार्वजनिक सेवा के लिए योग्यता, प्रतिबद्धता और जुनून के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि, कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

को बेहतर तरीके से समझा और हल किया जा सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप ऐसे नेताओं को तैयार करेगा जो राजनीति के क्षेत्र सहित पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ेंगे। देश में 21वीं सदी और खासकर पिछले 10 वर्षों में पैदा युवाओं की यह पीढ़ी सही मायने में भारत की पहली विकसित पीढ़ी होगी। उन्होंने इसे 'अमृत पीढी' कहा और विश्वास जताया कि 'सोल' इस 'अमृत पीढी' का नेतृत्व तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नए कौशल को अपनाने के लिए नेतृत्व विकास की जरूरत पर जोर

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मानव संसाधन सबसे अधिक सक्षम है। 21वीं सदी में ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार का नेतृत्व करने और कौशल को दिशा देने में सक्षम हों। श्री मोदी ने नए कौशल को अपनाने के लिए नेतृत्व विकास की जरूरत पर बल दिया और कहा कि इसे वैज्ञानिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोल ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसका लक्ष्य नेतृत्व विकास के लिए दुनिया की अग्रणी संस्था बनना है।

हर क्षेत्र में सर्वोत्तम नेतृत्व तैयार करने पर फोकस

श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जैसे दूरदर्शी नेता भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते थे और केवल 100 प्रभावी और कुशल नेताओं की मदद से इसका भाग्य बदलना चाहते थे। श्री मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को पुनर्जीवित करने और आगे बढ़ने के लिए इससे प्रेरणा लेने पर जोर दिया। उन्होंने 21वीं सदी के विकसित भारत के सपनों को सच करने के लिए 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में सभी क्षेत्रों में अच्छे नेतृत्व की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य का नेतृत्व केवल सत्ता तक सीमित नहीं होगा, बल्कि नेतृत्व की भूमिका के लिए नवाचार और प्रभाव की क्षमताओं की आवश्यकता होगी। नेतृत्व विकास के दौरान 'सोल' इन व्यक्तियों में आलोचनात्मक सोच, जोखिम लेने और समाधान-संचालित मानसिकता विकसित करेगा।

सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय उत्कृष्टता का आकांक्षी है भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे भारत कूटनीति से लेकर तकनीकी नवाचार तक के क्षेत्रों में नए नेतृत्व को आगे बढ़ाएगा, देश का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में कई गुना बढ़ जाएगा। श्री मोदी ने वैश्विक सोच को स्थानीय परवरिश के साथ जोड़कर आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया। शासन और नीति-निर्माण को विश्वस्तरीय बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह तब हासिल किया जा सकता है जब नीति निर्माता, नौकरशाह और उद्यमी वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों को शामिल करते हुए नीतियां बनाएं। सार्वजनिक नीति और सामाजिक क्षेत्रों में शक्ति और भावना विकसित करने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री मोदी ने डीप-टेक, अंतरिक्ष, बायोटेक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए नेतृत्व तैयार करने की बात की। उन्होंने खेल, कृषि, विनिर्माण और सामाजिक सेवा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के लिए नेतृत्व तैयार करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत को न केवल सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की आकांक्षा करनी चाहिए बल्कि इसे प्राप्त भी करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा, 'भारत को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, जो वैश्विक उत्कृष्टता के नए संस्थान विकसित कर सकें'।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27 वीं बैठक में बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

देश में शत प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के लिए सहकारिता ही एकमात्र विकल्प

सहकार उदय टीम

- देश के हर गांव में तीन किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखाओं व पोस्टल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य
- अंतर राज्य परिषद के दायरे में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर अपराध के विषयों को भी शामिल किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण केवल एक सूत्र नहीं, बल्कि एक संस्कृति बना है। हमने क्षेत्रीय परिषदों को सरकारी औपचारिकता से आगे बढ़कर एक रणनीतिक निर्णय लेने वाले मंच के रूप में स्थापित किया है, जिसके माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण और युग परिवर्तनकारी निर्णय लिए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के दौरान व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि देश में शत प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहकारिता ही एकमात्र विकल्प है। इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सुदृढ़ करने, उन्हें बहुआयामी बनाने व '*सहकार से समृद्धि*' की समग्र अवधारणा को पूरा करने के लिए किए गए 56 से अधिक पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्यों को जमीनी स्तर पर सहकारिता का एक मजबूत आधारभूत ढांचा बनाने के लिए हरसंभव कदम उठाना चाहिए।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में कुल 18 मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें भूमि हस्तानांतरण, खनन, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित

> पुणे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक राजधानी है। पुणे से युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज, अनेक महान पेशवाओं और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश को कई क्षेत्रों में समय-समय पर दिशा दिखाई।
>
> - श्री अमित शाह
>
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पश्चिम क्षेत्र देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण

श्री शाह ने कहा कि पश्चिम क्षेत्र देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के साथ देश का आधे से ज्यादा व्यापार पश्चिमी क्षेत्र से ही होता है। उत्तरी और मध्य क्षेत्र भी वैश्विक व्यापार के लिए पश्चिमी क्षेत्र पर ही निर्भर हैं। कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य भी पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम क्षेत्र की देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके साथ ही कई ऐसे उद्योग हैं जिनका 80 से 90 प्रतिशत काम इसी क्षेत्र में होता है। पश्चिमी क्षेत्र पूरे देश में संतुलित और समग्र विकास के लिए मानक स्थापित करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल राज्य देश के समृद्ध राज्यों में गिने जाते हैं, लेकिन इन राज्यों के बच्चों और नागरिकों में कुपोषण और उम्र के अनुरूप लंबाई नहीं बढ़ना चिंता की बात है। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के सभी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और मुख्य सचिवों से बच्चों और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन्हें कुपोषण से निजात दिलाने की अपील की और कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों और अस्पतालों से ही नहीं सुधरता, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चों और नागरिकों को इनकी जरूरत ही न पड़े। उन्होंने स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर कम करने और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया। तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि संविधान ने देश के नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, उन्हें हम नागरिकों तक शत प्रतिशत पहुंचाएं। आने वाले दिनों में अंतर राज्य परिषद के दायरे में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर अपराध के विषयों को भी शामिल किया जाएगा।

जांच, बलात्कार और पाक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का कार्यान्वयन, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के कार्यान्वयन, प्रत्येक गांवों में बैंक शाखाओं एवं पोस्टल बैंकिंग सुविधा, रेलवे परियोजना से संबंधित मुद्दे और खाद्य सुरक्षा मापदंड आदि शामिल हैं। इनके साथ ही, राष्ट्रीय महत्व के छह मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें शहरी मास्टर प्लान एवं किफायती आवास, विद्युत संचालन एवं आपूर्ति, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर कम करना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी और पैक्स को मजबूत करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। श्री शाह ने दलहन के आयात पर चिंता जाहिर करते हुए दलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।

सरकार ने एक ऐसा मोबाइल एप तैयार किया है जिसके माध्यम से भारत सरकार किसानों के शत प्रतिशत दलहन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद लेती है। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों से इस एप के प्रचार और इस पर किसानों के पंजीकरण पर जोर दिया, जिससे कि किसान अपने दलहन उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।

परिवर्तनकारी संस्था के रूप में काम कर रहीं क्षेत्रीय परिषदें

श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकारी है, लेकिन वर्ष 2014 में श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें क्षेत्रीय परिषदों को औपचारिक संस्थाओं की जगह परिवर्तन लाने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित करने में सफलता मिली है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के माध्यम से हमने संवाद, संपर्क और सहयोग के आधार पर समावेशी समाधान और समग्र विकास को सिद्ध करने का लक्ष्य हासिल किया है। श्री शाह ने कहा कि देश और राज्यों के दीर्घावधि आर्थिक विकास के लिए वर्तमान में किए गए प्रयास और भविष्य के रोडमैप के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं।

श्री शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वर्ष 2004 से 2014 तक के 10 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की केवल 25 बैठकें हुईं, जबकि मोदी सरकार के नेतृत्व में वर्ष 2014 से फरवरी 2025 तक कुल 61 बैठकें आयोजित की गईं, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले यह 140 प्रतिशत अधिक है। पिछली सरकार के 10 वर्षों के दौरान क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 469 विषयों पर चर्चा हुई, जबकि मोदी सरकार के सेवाकाल में अबतक 1541 मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जो कि पहले की अपेक्षा 170 प्रतिशत अधिक है। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों ने 2014 से फरवरी 2025 के बीच 1280 मामलों का निपटारा किया, जो कि पहले की सरकार ने 10 वर्षों में केवल 448 मुद्दों का ही निराकरण किया था। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में शामिल विषयों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश भर के प्रत्येक गांव में हर पांच किलोमीटर पर बैंक शाखाओं व पोस्टल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया गया है। अब देश के हर गांव के तीन किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखाओं व पोस्टल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया : प्रधानमंत्री श्री मोदी

'सबका इलाज- सबको आरोग्य' ही है 'सबका साथ-सबका विकास'

सहकार उदय टीम

- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी
- कैंसर हास्पिटल में वंचित वर्गों के मरीजों को मिलेगी नि:शुल्क चिकित्सा
- दूसरों की सेवा करना और उनके दुखों को दूर करना ही सच्चा धर्म : प्रधानमंत्री

जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तब मैंने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया। 'सबका साथ, सबका विकास' के इस संकल्प का भी एक बड़ा आधार है- सबका इलाज, सबको आरोग्य, जिसका अर्थ है सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न स्तरों पर बीमारी की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखने के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक केंद्र बागेश्वर धाम जल्द ही आरोग्य केंद्र भी बनेगा। बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान 10 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा तैयार होगी। जिले के गढ़ा गांव में इस चिकित्सा संस्थान के निर्माण से सभी वर्गों के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस कैंसर अस्पताल में वंचित वर्गों के कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाएगी। यह संस्थान अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से युक्त होगा। श्री मोदी ने कहा कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर संस्थान की स्थापना के नेक काम के रूप में समाज और मानवता के कल्याण के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। इसके परिणाम के रूप में बागेश्वर धाम में अब भक्ति, पोषण और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने देश और धर्म को मजबूत करने की दिशा में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि वे लंबे समय से देश में एकता के मंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि पूरे भारत में बड़े अस्पतालों के संचालन में धार्मिक संस्थाओं की अहम भूमिका है। देश में बहुत से स्वास्थ्य और विज्ञान अनुसंधान संस्थान धार्मिक ट्रस्टों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो करोड़ों गरीब लोगों को उपचार और सेवा प्रदान करते हैं। भगवान राम से जुड़ा बुंदेलखंड का पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट दिव्यांगों और रोगियों की सेवा

का एक प्रमुख केंद्र है। उन्होंने खुशी जताई कि बागेश्वर धाम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देकर इस गौरवशाली परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। श्री मोदी ने महाशिवरात्रि के महापर्व पर 251 बेटियों के सामूहिक विवाह की नेक पहल के लिए भी बागेश्वर धाम की सराहना की।

विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र हैं भारत के मठ-मंदिर

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में मठ व मंदिर पूजन और साधन के केंद्र होने के साथ ही विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ही आयुर्वेद और योग का विज्ञान दिया, जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरों की सेवा करना और उनके दुखों को दूर करना ही सच्चा धर्म है। 'नारायण में नर' और 'सभी प्राणियों में शिव' की भावना के साथ सभी जीवों की सेवा करने की भारतीय परंपरा पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयाग महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। इसे ''एकता का महाकुंभ'' बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान 'नेत्र महाकुंभ' भी आयोजित हुआ और दो लाख से अधिक तीर्थयात्रियों की नेत्र जांच की गई और करीब डेढ़ लाख लोगों को मुफ्त दवा और चश्मा दिया गया। वहीं, लगभग सोलह हजार रोगियों को मोतियाबिंद और अन्य सर्जरी के लिए विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के दौरान होने वाली स्वास्थ्य और सेवा से संबंधित कई पहलों को जिक्र किया, जिसमें हजारों डॉक्टरों और स्वयंसेवकों ने निस्वार्थ भाव से भाग लिया।

सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हमारा शरीर और स्वास्थ्य ही हमारे धर्म, सुख और सफलता को प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है। वर्ष 2014 में सरकार के गठन के साथ ही उन्होंने देश के गरीब परिवारों के इलाज के खर्च को कम करने और लोगों के लिए ज्यादा पैसे बचाने का संकल्प लिया था। श्री मोदी ने देश के सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार ने चिकित्सा व्यय के बोझ को कम किया है और आयुष्मान कार्ड के जरिए हर गरीब व्यक्ति के लिए पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के देश के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें बिना किसी खर्च के ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दवाओं की लागत कम करने के लिए देश भर में 14,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं। श्री मोदी ने कहा कि किडनी की बीमारी की गंभीर समस्या के निदान के लिए देश के 700 से अधिक जिलों में 1,500 से अधिक डायलिसिस केंद्र खोले गए हैं, जो मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान करते हैं।

देश के सभी जिलों में खुलेंगे कैंसर डे-केयर सेंटर

श्री मोदी ने कहा, ''कैंसर हर जगह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है; सरकार, समाज और संत सभी कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं।'' कैंसर से निपटने के लिए सरकार ने प्रयासों को तेज किया है और इस साल के बजट में कई घोषणाएं की हैं। सरकार कैंसर की दवाओं को और अधिक किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने अगले तीन वर्षों में हर जिले में कैंसर डेकेयर सेंटर खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि ये केंद्र निदान और राहत देखभाल सेवाएं प्रदान करेंगे। कैंसर से बचाव के लिए सतर्क और जागरूक रहने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि समय रहते इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार कैंसर फैल जाने पर उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए चल रहे अभियान का जिक्र कर उन्होंने सभी देशवासियों से इसमें भाग लेने और लापरवाही से बचने का आग्रह किया।

बुंदेलखंड की समृद्धि के लिए सरकार संकल्पित

जन सेवा के प्रति अपने समर्पण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छतरपुर की पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। बुंदेलखंड में क्षेत्र में पानी की कमी को 45,000 करोड़ रुपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना दूर करेगी। पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन व हर घर जल परियोजना के तहत बुंदेलखंड के गांवों में पाइप से पानी की आपूर्ति की जा रही है। बुंदेलखंड की समृद्धि के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसे पहल किए गए हैं। श्री मोदी ने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की घोषणा की और कहा कि महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बुंदेलखंड में सिंचाई का पानी पहुंचने के बाद फसलों पर छिड़काव और खेती में मदद मिलेगी। किसानों की कठिनाइयों को कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार दिन-रात अथक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों से बुंदेलखंड और भारत की समृद्धि सुनिश्चित होगी। ■

सरकारी पहलों से युवाओं की उद्यमिता में बढ़ी रुचि

डॉ नेहा चौधरी/डॉ ममता वर्मा

भारत उन पांच देशों में से एक है जहां विशेषज्ञ महिला उद्यमियों के लिए सामाजिक सहयोग और संसाधन उपलब्धता को पर्याप्त या बेहतर मानते हैं। वैश्विक उद्यमिता मॉनीटर (ग्लोबल इंटरप्रन्योरशिप मॉनीटर जीईएम) वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत विश्वभर के उन 49 देशों में शामिल हो गया है, जिन्हें व्यवसाय या व्यापार करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। यह जानकारी एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिन्हें भारतीय पेशेवरों से 13 उद्यमिता रूपरेखा शर्तों (ईएफसी) के आधार पर देश का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था।

उद्यमिता रूपरेखा शर्तों में सामाजिक और सांस्कृतिक मानकों को प्रमुखता से शामिल किया गया, जो उद्यमिता और उद्यमिता शिक्षा को स्कूल और स्कूल के बाद की शिक्षा में शामिल करने पर जोर देता है। इस रिपोर्ट में भारत की यह रेटिंग एक साल में चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।

वैश्विक उद्यमिता मॉनीटर (जीईएम) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल उद्यमशीलता गतिविधि दर (व्यस्कों 18-64 उम्र में) का अनुपात जो नई फर्म शुरू कर रहे हैं या उनका संचालन कर रहे हैं वर्ष 2020 में 5.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 15.4 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त 18 से 64 साल की आयुवर्ग के ऐसे लोगों का प्रतिशत भी बढ़ा है जो अब एक स्थापित व्यवसाय के मालिक- प्रबंधक का पद संभाल रहे हैं और अपने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान भी कर रहे हैं।

नये व्यवसायों को बढ़ाने में सरकार की भूमिका

भारत धीरे धीरे एक मजबूत स्टार्टअप परिदृश्य का निर्माण कर रहा है। उद्यमिता को बढ़ावा देने और उद्यमियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा एक मंत्रालय का गठन किया गया है, जो पूरी तरह देश में स्व रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और देश पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशा निर्देश में युवाओं को उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है। सरकार की पहलें युवाओं के लिए कारगर साबित हो रही हैं। *सहकार से समृद्धि* के संकल्प को पूरा करते हुए सहकारिता में भी उद्यमिता विकास संभव है यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी नीति से ही संभव हुआ। नई फर्म और कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की सहायक पहलें की गईं, इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिससे नई फर्म को सीड फंडिंग और अन्य तरह की वित्तीय सहायता मिल सके। सरकार ने कंपनियों को नेटवर्किंग, संसाधन तक पहुंच और सलाह देने में मदद करने के लिए इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर भी स्थापित किए हैं। ये एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर नए व्यवसायों को उनकी अवधारणाओं और वस्तुओं को विकसित करने के लिए जरूरी सहायता और संसाधन प्रदान करते हैं।

स्टार्टअप को दी जाने वाली सहायता पहलें

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा कंपनियें और फर्मो को राष्ट्रीय स्तर की सहायता प्रदान की जाती है। जिनमें से कुछ पहलें इस प्रकार हैं-

स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान- जनवरी 2016 में देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान शुरू किया गया। जिसके तहत 19 बिंदुओं को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन, उद्योगों के साथ शैक्षणिक साझेदारी व इंक्यूबेशन इसके साथ ही सरलीकरण और सहायता आदि पर सहायता दी गई। देश में स्टार्टअप के लिए एक मजबूत पारिस्थितितंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया।

एफएफएस (स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स) स्कीम- व्यवसायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने

10 हजार करोड़ रुपए का एफएफएस या फंड ऑफ फंड्स कोष स्थापित किया गया। डीपीआईआईटी (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड) संस्थानों की निगरानी करता है, वहीं सिडबी (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) उद्यमों को ऋण की सहायता उपलब्ध कराने व योजनाओं के तहत वितरित किए गए ऋण की मॉनिटरिंग करता है। 14 व 15वें वित्तीय कमिशन चरण में कुल 10 हजार करोड़ रुपए के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय सहायता ने नये उद्यमों के लिए पूंजी कोष का काम किया, जिससे स्टार्टअप की विदेशों से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम हुई। स्टार्ट की सीड फंडिंग के अतिरिक्त सरकार ने नये और स्थानीय उद्यमों के विकास के लिए भी ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की।

स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस)- डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए सरकारी वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का संचालन किया जाता है। इनमें नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनीज और वेंचर डेबिट फंड्स सेबी द्वारा अधिकृत बैंक के माध्यम से वैकल्पिक निवेश फंड मुहैया कराते हैं। स्कीम के तहत मेंबर इंस्टीट्यूट (एमआई) द्वारा पात्र उधारकताओं को विशेष रूप से डीपीआईआईटी द्वारा अनुमोदित स्टार्टअप को जारी किए गए ऋणों के विरूद्ध एक निश्चित राशि तक ऋण गारंटी प्रदान करना है।

विनियामक सुधार- स्टार्ट के लिए उपयुक्त वातावरण स्थापित करने, समस्याओं के निराकरण, पूंजी का हस्तांतरण और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 50 से भी अधिक विनियामक सुधारों को वर्ष 2016 से ही शुरू किया गया है।

खरीददारी में आसानी- खरीद में आसानी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि डीपीआईआईटी द्वारा अनुमोदित किसी भी स्टार्टअ के लिए सार्वजनिक खरीद में पिछले टर्नओवर और पिछले अनुभव के प्रतिबंधों को शिथिल करें, जबतक कि

तकनीकी और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। उद्यमियों के लिए सरकार को सीधे उत्पाद और सेवाएं बेचने के लिए एक समर्पित स्थान बनाया गया है, जिसे गर्वमेंट ई मार्केटप्लेस स्टार्टअप रनवे कहा जाता है।

उपरोक्त सभी पहलें देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गईं। इसके अतिरिक्त युवाओं के पास स्टार्टअप इंडिया प्लेटफार्म के माध्यम से अपना स्टार्टअप शुरू करने के कई विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। जिनकी सहायता से छात्र कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर स्टार्टअप स्किल को बढ़ा सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और उनका जीवन भी बेहतर होगा। इससे जीडीपी में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा और जीवन स्तर में सुधार होगा। प्रत्येक नए व्यवसाय द्वारा लाए गए रोजगार के अवसरों और विशेष कौशल के विस्तार से अधिक आर्थिक वृद्धि और विकास भी होगा।

आर्थिक विकास और प्रगति उद्यमिता पर बहुत अधिक निर्भर करती है क्योंकि यह नवाचार को प्रोत्साहित करती है, रोजगार पैदा करती है और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। नई कंपनियों को लॉन्च करने और चलाने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने वाले सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए, उद्यमी जोखिम उठाते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि उद्यमिता से काफी प्रभावित हुई है। इसकी बदौलत अब लाखों लोगों के पास काम है और इसने अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, इसने विदेशियों के लिए नए बाजार और निवेश के अवसर खोले हैं। अवसरों को खोजना और उन्हें भुनाने के लिए जोखिम उठाना उद्यमिता की नींव है। उद्यमियों को कल्पनाशील, दूरदर्शी और नए विचारों और बदलते बाजार की गतिशीलता के साथ समायोजन करने के तरीकों के प्रति ग्रहणशील होने की आवश्यकता है। अपने व्यवसाय का समर्थन करने के लिए, उन्हें एक ठोस टीम को इकट्ठा करने और संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में भी सक्षम होना चाहिए।

आर्थिक विकास और प्रगति, उद्यमिता पर बहुत अधिक निर्भर करती है क्योंकि यह नवाचारों को प्रोत्साहित करती है, रोजगार पैदा करती है और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। नई कंपनियों को लॉन्च करने और चलाने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने वाले सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए, उद्यमी जोखिम उठाते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि उद्यमिता से काफी प्रभावित हुई है। इसकी बदौलत अब लाखों लोगों के पास काम है और इसने अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, इसने विदेशियों के लिए नए बाजार और निवेश के अवसर खोले हैं। अवसरों को खोजना और उन्हें भुनाने के लिए जोखिम उठाना उद्यमिता की नींव है। ■

प्रवक्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव प्रबंधन, जयपुर, राजस्थान

संकाय सदस्य, पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी, सीकर, राजस्थान

महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियां भारत में आर्थिक विकास को दे रही हैं बढ़ावा: संघाणी

सहकार उदय टीम

भारत को विकसित बनाने में सहकारी समितियों का अहम योगदान होगा, *सहकार से समृद्धि* के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में कई अहम पहलें की गईं। सहकारिता देश में महिलाओं को स्वावलंब बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी क्रम में विकसित भारत में महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के योगदान विषय पर गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन द्वारा राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

➲ द गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन ने राज्य स्तरीय महिला कोऑपरेटिव सेमिनार का आयोजन किया

गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष जी एच अमीन ने सेमिनार की अध्यक्षता की, जबकि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के अध्यक्ष और इफको के चेयरमैन दिलीप संघाणी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री संघाणी ने कहा कि कहा कि सहयोग हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है और अमूल जैसे सफल सहकारी संस्थाओं ने देश में सफल सहकारिता मॉडल सहकारिता के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। सहकारिता क्षेत्र रोजगार के अनगित अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हैं लेकिन सहकारिता में पहले महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी। अपने संबोधन में जीएच आमीन ने लैंगिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देशभर की 8.5 लाख सहकारी समितियों में केवल 25,385 सहकारी समितियां ही महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। इस आधार पर सहकारिता में महिलाओं की संख्या पुरूषों के अनुपात में कम है। उन्होंने महिलाओं से सहकारिता में भागीदारी बढ़ाने और नेतृत्व की भूमिका में शामिल होने पर जोर दिया। आमीन ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी (2008-2010) के दौरान सहकारी जहां कॉरपोरेट व्यवसाय नुकसान झेल रही थे, सहकारी समितियां लाभ का कारोबार कर रही थीं। उन्होंने इस स्थिरता को सहकारी समितियों की वैश्विक मान्यता से जोड़ा और 2012 और 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के निर्णय की सराहना की।

सेमिनार में सहकारिता को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महत्वपूर्ण सहयोग के महत्व को भी बताया गया। प्रधानमंत्री की दूरगामी रणनीति के तहत वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने की औपचारिक घोषणा नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन के दौरान की गई। श्री आमीन ने कहा कि सहकारिता में सक्रिय भागीदारी से महिलाएं भारत को विकसित बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती हैं। एनसीयूआई के राष्ट्रीय कोऑपरेटिव कमेटी फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन की निदेशक आरती बिसारियां ने इस अवसर पर सामाजिक समरसता विषय पर पुस्तक का विमोचन किया और दोहराया कि सहकारिता महिलाओं के आत्म-सम्मान और सतत विकास का प्रमुख माध्यम है। उन्होंने गुजरात के आर्थिक विकास में महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी समितियों के योगदान को प्रमुख बताया और कहा कि सहकारिता के गुजरात में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां महिलाएं सहकारी समितियों का नेतृत्व कर रही हैं।

सेमिनार में विशेषज्ञ वक्ताओं ने सहकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। डॉ. भूमिबेन पंड्या (महिलाओं में कौशल विकास), सुश्री अनीता कपूर (महिला नेतृत्व), सुश्री दृष्टिबेन ओझा (सरकारी योजनाएं), और सुश्री वर्षाबेन मोरे (डेयरी उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास) सहित कार्यक्रम में विभिन्न सहकारी समितियों की लगभग 1,300 महिला सदस्यों ने भाग लिया।

एआई और सेंसर उपकरण से डिजिटल होगी सहकारिता

सहकार उदय टीम

उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्राप और डिजिटल मैपिंग के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। कृषि क्षेत्र की सहकारी समितियों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी सेंसर मैपिंग सहित एआई कृत्रिम बुद्धिमता का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम ने आईसीड, इरमा और आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से टिहान (टीआईएचएएन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन) प्रोजक्ट शुरू किया गया। तकनीकी साझेदारी से देश में डिजिटल क्रॉप और जियोपार्शियल नेविगेशन का प्रयोग संभव होगा। मालूम हो कि वर्ष 2024-25 के आम बजट में उन्नत कृषि के लिए कृषि की डिजिटल मैंपिंग को प्रमुख रूप से शामिल किया गया।

- द वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम, इरमा और आईआईटी हैदराबाद ने कृषि सहकारिता में तकनीकी और डिजिटल प्रयोगों की पहल की
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और एआई के इस्तेमाल से पीएम के डिजिटल क्राप का सपना होगा पूरा

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सहकारिता को बेहतर करने की दिशा में किए गए तकनीकी प्रयोग निश्चित रूप से सहकारिता को बेहतर करने में कारगर होगें। इससे *सहकार से समृद्धि* के संकल्प को पूरा करने के साथ ही ग्रामीण सहकारिता, आर्थिक विकास और सतत आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। उन्नत सेंसर उपकरण और एआई के प्रयोगों के डेयरी सहकारिता, कृषि सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों की उत्पादकता तथा कार्यप्रणाली को और बेहतर किया जा सकेगा। द वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम (डब्लूसीओओपीईएफ) के चेयरमैन दिलीप संघाणी ने कहा कि यह पहल सहकारी कृषि और ग्रामीण उद्यमों में डेटा-संचालित निर्णय लेने, एआई-संचालित भू- बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ टाइमिंग-आधारित वास्तविक समय डेटा संग्रह और डिजिटल मानचित्रण को एकीकृत करेगी। श्री संघाणी ने कहा कि देश में सहकारिता मॉडल कृषि क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है जीओपार्शियल इनोवेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या सेंसर आधारित डिजिटल उपकरणों के प्रयोग व क्राप सर्वेक्षणों को एकीकृत करने से सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण होगा, जिससे वे डेटा-संचालित, कुशल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी। श्री दिलीप संघाणी ने कहा कि कृषि सहकार क्षेत्र में तकनीकी का इस तरह से प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के *सहकार से समृद्धि* और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। तकनीक और एआई के इस्तेमाल से छोटे और सीमांत किसानों सटीक फसल उत्पादन का लाभ मिलेगा, बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गठित पीएम हाई पॉवर कमेटी के सदस्य और डब्लूसीओओपीईएफ के संस्थापक अध्यक्ष बिनोद आनंद ने कृषि में डिजिटल प्रयोगों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया, और कहा कि हमें तकनीकी आधारित उद्यमिता को अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे ग्रामीण और छोटे किसानों की आजीविका बेहतर हो रही है। श्री बिनोद आनंद ने कहा कि इस पहल के तहत डिजिटल क्राप सर्वेक्षण के लिए आईओटी तकनीक आधारित इकोनॉमिक जोन विकसित किया जाएगा। एआई आधारित जीओ पार्शियल बुद्धिमत्ता और रियल टाइम मार्केट लिंकेज से सहकारिता का पारिस्थितिकीतंत्र मजबूत होगा और सतत आजीविका का मार्ग प्रशस्त होगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में यह पहले स्मार्ट संसाधन प्रबंधन, डेटा संचालित निर्णय लेने और खरीद योजनाओं पर केंद्रित बैठकों के माध्यम से कृषि और किसान सहकारी समितियों के लिए सक्षम सेवाओं की शुरूआत करेगी। कौशल विकास और नवाचार केंद्रीय होगें, जिसमें एक डिजिटल ज्ञान मंच की स्थापना होगी।

स्मार्ट संसाधन प्रबंधन में मिट्टी, पानी और जलवायु डेटा प्रबंधन, फसल योजना, सिंचाई और आपूर्ति श्रंखला को अनुकूलित करने के लिए इंटरनेट ऑफ टाइमिंग सेंसर, उपग्रह, इमेजनरी और एआई विश्लेषण आदि शामिल होगें। इसके अतिकार रिक्त, बाजार पहुंच पहल और वित्तीय समावेशन का विस्तार करने, आपदा लचीलापन और जलवायु अनुकूलन आदि रणनीतियों को मजबूत करने और छोटे किसानों का सहयोग करने के लिए सटीक कृषि को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

International Year 2025 of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

डॉ एआर श्रीनाथ

सहकारिता से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर बल

विश्व में सहकारिता आंदोलन कई मायने में लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। भारत में सहकारिता आंदोलन लोगों के जीवन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का विस्तार निचले स्तर तक हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा सहकारिता आंदोलन को और भी अधिक मजबूत बनाने की है, जिसमें देश के युवा, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है। महिलाओं, युवाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को भी अधिक से अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। विश्व भर की सहकारी समितियों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और महिलाएं सहकारी समितियों में नेतृत्व की भूमिका में आगे आ रही हैं।

भारत के विभिन्न सेक्टरों में साढ़े आठ लाख सहकारी समितियां हैं, जिससे 29 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद देश में बड़ी आबादी को रोजगार की दरकार है। बेरोजगारी खत्म करने और गरीबी दूर करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहकारिता की भूमिका लगातार बढ़ी है, जिसमें महिलाओं की अब महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाएं अब विभिन्न तरह की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले रही हैं। सहकारी समितियां महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और पारिवारिक आमदनी में सहयोग करने का माध्यम बन गई है। पंचायती राज कानूनों में संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थानीय निकाय और नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एमएससीएस (बहु राज्य सहकारी समिति) अधिनियम 2023 में सहकारी समितियों के निदेशक मंडल में दो महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं का काफी सराहनीय योगदान रहा है। एनसीयूआई द्वारा विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए शैक्षणिक फील्ड प्रोजेक्ट कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

एनसीयूआई विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे आत्मनिर्भर हो रही हैं। भोपाल, शिमोगा और इंफाल में महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सशक्त करने के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। छह जुलाई वर्ष 2021 में गठित किए गए देश के पहले सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से भारतीय महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इस क्रम में आम बजट में महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रूपए के बजट का स्वीकृत किया गया, जिससे महिला और लड़कियों के जीवन को बेहतर करने में खर्च किया जाएगा। इससे यह सिद्ध होता कि सरकार आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को मजबूत करने के अपने संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकास में महिलाओं की सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही लघु, सुक्ष्म और मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस संदर्भ में सहकारी क्षेत्र इन योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं के विकास के लिए पंजीकृत सहकारी समितियां जैसे कि महिला कल्याण सहकारी समितियां (जिनमें से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस रिपोर्ट के अनुसार 25,092 हैं) विकास के लिए इन निधियों तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। इसका प्रयोग महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के अधिक आयोजन करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों उद्यमों की बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय युवाओं के लिए भी सहकारिता में बेहतर भविष्य के अपार विकल्प उपलब्ध हैं। भारतीय शहर में हर तीसरा व्यक्ति युवा है, जल्द ही भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने वाला है, जिसकी 64 प्रतिशत आबादी कामकाजी आयु वर्ग की है। अभी अधिकांश भारतीय युवा शैक्षणिक स्तर पर सहकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हैं।

युवा उत्पाद या सेवा आधारित सहकारी समिति शुरू कर सकते हैं, इससे सहकारिता के संदर्भ में उनकी शिक्षा का अधिक बेहतर उपयोग किया जा सकता है। हालांकि अभी तक युवाओं की सहकारिता में भागीदारी कैंपस गतिविधियों तक ही सीमित हैं, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों में युवा छोटी लेकिन जरूरी चीजों की आपूर्ति चेन बनाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं जैसे कैंपस में कॉपी, किताब, पेन पेंसिल आदि की बिक्री युवाओं की छोटी सहकारी समितियों द्वारा की जा रही है। यह सहकारी समितियां अन्य जरूरी सेवाएं जैसे टिकट बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि सेवाओं का भी संचालन कर रही हैं। बहुत कम जगहों पर यह युवा बचत और ऋण संबंधी गतिविधियों को भी संचालित कर रही हैं। उम्मीद यह भी की जा रही है कि नई सहकारिता नीति से सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना से सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।■

पूर्व निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई)

केन्या के सहकारिता विश्वविद्यालय द्वारा एक उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और वैश्विक साझेदारी सहित कई विषयों पर विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों ने बात की। सेमिनार में केन्या के सहकारिता आयुक्त डेविड ओबोनयो, एनसीयूआई के चेयरमैन श्री दिलीप संघाणी सहित वैश्विक सहकारिता जगत के कई बड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इफको के प्रबंध निदेशक डॉ उदय शंकर अवस्थी ने अपनी जॉर्डन यात्रा के दौरान जेपीएससी (जॉर्डन फॉस्फेट माइन्स कंपनी) की बोर्ड बैठक में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने प्लांट के उत्पादन और लाभप्रदता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। डॉ अवस्थी ने बेहतर काम करने के लिए जेपीएमसी की टीम को बधाई दी।

पुणे के वैमनीकॉम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए इफको के कृषि वैज्ञानिक डॉ एसएस पवार ने सहकारी डिजिटल नवाचार और मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से समृद्धि विषय पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में सहकारी समितियों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इफको के विपणन निदेशक श्री योगेन्द्र कुमार ने पलवल के किसान श्री धर्मपाल, श्री टेकन और श्री कृष्ण से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी फसलों में इफको नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल किया था। किसानों ने कहा कि नैनो यूरिया के प्रयोग के उन्हें बेहतर परिणाम मिले हैं। किसान पारंपरिक यूरिया की जगह अब नैनो यूरिया और डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं।

इफको ने 17वें कृषि विज्ञान कांग्रेस और एएससी एक्सपो के दौरान जीबीपीयूए एंड टी पंतनगर, उत्तराखंड में किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर इफको के मार्केटिंग विभाग के रजनीश पांडे ने किसानों को इफको नैनो उर्वरक व डीएपी के बारे में जानकारी दी। एक्सपो में कृषि ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर इफको ने नई दिल्ली स्थित इफको सदन में जांबिया के प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की। इसका नेतृत्व जांबिया गणराज्य के लघु एवं मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय की श्रीमती सुबेटा के मुटेलो ने किया। इस अवसर पर इफको के प्रबंध निदेशक डॉ उदय शंकर अवस्थी सहित कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे।

"विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट हैं। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं, जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे, हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं, पहला- कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा- हमारे गांवों की समृद्धि।"

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

Published on 08th April
"Sahkar Uday"

RNI No. DELHIN/2024/88557
Postal Registration No.: DL(S)-17/3560/2024-26

Posting date : 08th-12th April
Posted at : Lodhi Road HO, New Delhi-110003